



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 95]
No. 95]

नई दिल्ली, सोमवार, मई 24, 2004/ज्येष्ठ 3, 1926
NEW DELHI, MONDAY, MAY 24, 2004/JYAISTHA 3, 1926

महापत्रन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

मुंबई 19 मई, 2004

सं. टीएमपी/79/2003-टीपीटी.—महापत्रन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 49 और 50 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महापत्रन प्रशुल्क प्राधिकरण एतद्वारा, तूतीकोरिन पत्रन न्यास (टीपीटी) से, विद्युत प्रभारों के संबंध में उपरिव्यव प्रभार की वसूली के लिए लेवी निर्धारित करने हेतु प्राप्त प्रस्ताव को संलग्न आदेशानुसार निपटाता है।

सं. टीएमपी/79/2003-टीपीटी.

तूतीकोरिन पत्रन न्यास (टीपीटी)

आवेदक

आवेदक
(मई 2004 के 4 थे दिन पारित)

यह प्रकरण विद्युत प्रभारों के संबंध में उपरिव्यव की वसूली के लिए लेवी निर्धारित करने हेतु तूतीकोरिन पत्रन न्यास (टीपीटी) से प्राप्त प्रस्ताव के बारे में है।

2.1. टीपीटी ने अपने प्रस्ताव में निम्नलिखित मुख्य बातें प्रस्तुत की हैं :

- (i) उपभोक्ताओं / उपयोगकर्ताओं द्वारा उपयोग की गई विजली के संबंध में प्रभार तमिलनाडु विद्युत बोर्ड (टीएनईबी) द्वारा निर्धारित प्रशुल्क के अनुसार एकात्रित किए जाते हैं।
पीएसए एसआईसीएसल के मालिये में एक अलग ट्रॉस्कोर्प गैजूद है। इस प्रकार खपत प्रभारों के अलावा, अधिकतम मांग प्रभार और मीटर किराया भी पीएसए एसआईसीएसल से लिए जाते हैं।

(ii) उपरोक्ताओं को विद्युत का वितरण करते समय पत्तन अधिकतम मांग प्रभारों, वितरण के लिए प्रदत्त बुनियादी संरचना पर, वितरण क्षमता और प्रचालन तथा अनुरक्षण लागत पर भारी खर्च करता है। अतएव, उपरोक्ताओं से उपरिव्यव प्रभार वसूलने का प्रस्ताव है। चूंकि, उपरिव्यव वसूल करने के लिए पत्तन द्वारा जून 2003 में आकलित दर न्यासी मंडल के सदस्यों को स्वीकार नहीं थी, उपरोगकर्त्ताओं द्वारा प्रयुक्त विजली के संबंध में उपरिव्यव प्रभार के रूप में वसूले जाने के लिए लेवी की सिफारिश करने हेतु तीन सदस्यीय दल का गठन किया गया था।

(iii) समिति द्वारा प्रस्तुत लागत मण्डन के अनुसार, कुल उपरिव्यव की वसूली के लिए विद्युत प्रभार का 142.77% पीएसए एसआईसीएएल से 158.09% अन्य उपरोगकर्त्ताओं से वसूल किया जाना है। इस संदर्भ में, उसने बताया है कि विद्युत उपरिव्यव प्रभार के रूप में सीओपीटी द्वारा 291% और जवाहर लाल नेहरू पत्तन न्यास द्वारा 20% प्रभार लगाया जाता है।

(iv) बड़ी गांव में अप्रत्यक्ष लागत सम्प्रिलित होने को व्यान में रखते हुए, समिति ने, तत्पश्चात, केवल प्रत्यक्ष लागत 52.55% की दर से पत्तन उपरोगकर्त्ताओं से और 33.62% की दर से पीएसए एसआईसीएएल से वसूलने का प्रस्ताव किया था।

(v) समिति के दो सदस्यों ने इस घटी दर पर भी आपत्ति की थी और लेवी की वसूली 5% की नाम मात्र की दर पर करने का सुझाव दिया था। समिति के सदस्यों ने उल्लेख किया कि उपरोगकर्त्ता पत्तन से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद विद्युत आपूर्ति सीधे तमिलनाडु विद्युत बोर्ड से प्राप्त करना चाहेंगे।

2.2. टीपीटी के न्यासी मंडल ने पत्तन उपरोगकर्त्ताओं, टेकेदार इत्यादियों से उपरिव्यव प्रभार की वसूली के लिए तदर्थ आधार पर विद्युत बिल के 20% की दर से वसूल करने को अन्तरोगत्वा अपनी स्वीकृति दे दी। पत्तन ने यह कहा है कि प्रस्तावित लेवी की बाद में समीक्षा की जाएगी।

3.1. अपनाई गई परामर्शी प्रक्रिया के अनुसार प्रस्ताव की एक प्रति उपरोगकर्त्ता संगठनों को उनकी टिथ्पी के लिए भेजी गई थी।

3.2. उपरोक्त उपरोगकर्त्ताओं से प्राप्त टिप्पणियाँ प्रतिपूरक सूचनाओं के रूप में टीपीटी को भेजी गई थी। प्रत्युतर में, टीपीटी ने अपनी टिप्पणियाँ निम्नानुसार प्रस्तुत की हैं:-

(i) टीपीटी के साथ किए गए पट्टा-अनुबंध के अनुसार तूतीकोरिन स्टीमर एजेन्ट्स एसोसिएशन (टीएसए) को, पत्तन द्वारा समय-समय पर निर्धारित प्रशुल्क को वहन करना होगा। अपने दावे के समर्थन में अनुबंध की प्रति संलग्न की गई है।

(ii) जहाँ तक टीएसए की इस ट्रेसा का सवध है कि पत्तन ने समुचित और्जित्य प्रस्तुत नहीं किया है, इसने स्पष्ट किया है कि पत्तन टीएन्डबी को भुगतान किए गए प्रशुल्क के अलावा, मरम्मत और अनुरक्षण (जिसमें नियुक्त किए गए कर्मचारियों के स्थापना प्रभार भी सम्भिलित हैं) और विद्युत संस्थानों के लागत अवमूल्यन पर भी व्यय करता है। इसकी वसूली भुक्तियाँ प्राप्त करने वाले उपरोगकर्त्ताओं से वसूल की जानी है।

(iii) इसने प्रस्तावित लेवी के विधिक प्राक्षणों को स्पष्ट करने के लिए विद्युत अधिनियम 2003 को विभिन्न धाराओं का निम्नानुसार संदर्भ दिया है:

मांग -IV- लाइसेंसिंग

खंड संख्या 13-छूट प्रदान करने की शक्ति

“समुचित सरकार की सिफारिशों पर समुचित आयोग, राष्ट्रीय नीतियों के अनुसार, खंड 5 के अधीन और जनहित में अधिसूचना द्वारा निदेश दे सकता है कि ऐसी शर्तों और पाबन्दियों के अधीन, यदि कोई हो और ऐसी अवधि या अवधियों के तिर, जो अधिसूचना में विविहित की जा सकती है, खंड 12 के प्राक्षण किसी स्थानीय प्राधिकरण पंचायत संस्थान, उपरोगकर्त्ता एसोसिएशन, सहकारी सोसायटियों, गैर-सरकारी संगठनों या विशेषाधिकार प्राप्तों पर लागू नहीं होंगे।”

खंड सं. 41

“स्थानीय प्राधिकरण” से अभिप्राय किसी नगर पंचायत, नगरपालिका, नगर निगम, ग्राम स्तर पर गठित पंचायत, मध्यकर्ता या जिला स्तरीय निकाय या पत्तन आयुक्त या अन्य प्राधिकारी जो कानूनी तौर पर अधिकारी हो, या संघ या किसी राज्य सरकार द्वारा किसी क्षेत्र या स्थानीय कोष के नियंत्रण या प्रबंधन के लिए न्यस्त किया गया हो, से है।”

खंड सं. 184

इस अधिनियम के प्राक्षण केन्द्र सरकार के रक्षा, परमाणु ऊर्जा से सम्बद्ध मंत्रालय या विभाग पर या ऐसे ही समान मंत्रालयों, विभागों या ऐसे मंत्रालयों या विभागों के नियंत्रणाधीन उपक्रमों या बोर्डों या संस्थानों पर, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाएं, लागू नहीं होंगे।”

विद्युत अधिनियम 2003 में उपरोक्त प्राक्षणों के अनुसार, यह स्पष्ट है कि विद्युत के पारेषण, वितरण आदि के लिए एक अधिकृत व्यक्ति होने हेतु, लाइसेंस प्राप्त करने का प्राक्षण किसी स्थानीय प्राधिकारी पर लागू नहीं होगा और “स्थानीय प्राधिकारी” शब्द की परिभ्रान्ति में अन्य निकायों के साथ-साथ पत्तन आयुक्त भी शामिल है।

(iv) इसके अलावा, इसने अपने दावे के समर्थन में टीएनईबी के साथ विद्युत आपूर्ति के लिए हुए अनुबंध की शर्तों और निबंधनों का भी संदर्भ दिया है। इस दस्तावेज में धारा 31.03(1) और (2) इस प्रकार है:-
 “परिसर का निर्माता या प्रोन्नतकर्ता को, जिसके नाम से आपूर्ति जारी है, पर्सों के अलग-अलग स्वामियों आदि को या पट्टेदारों को, सब-ग्रीटर लगाकर विद्युत आपूर्ति पहुँचाने और उनसे बिना हानि-लाभ के आधार पर विद्युत के उपयोग की लायत करने के अन्यत विद्युत के उपयोग के ब्याय में हिस्सा बाटने) की अनुमति दी जा सकती है और इसे विद्युत आपूर्ति का अनधिकृत विस्तार या विद्युत आपूर्ति की अनधिकृत विकी नहीं मारी जाएगी।”
 पत्तन उपयोगकर्ताओं को विद्युत की आपूर्ति पहुँचा रहा है। इस धारा के अनुसार पत्तन विद्युत के उपयोग के लिए देश राशि के अतिरिक्त, हानि-लाभ रहित आधार पर, किए गए व्यय की वसूली के लिए प्रभार एकत्रित कर सकता है।

(v) अधिकतम मांग प्रभार लगातार बढ़ रहा है और अनुरक्षण और स्थापना प्रभारों में भी भरपूर वृद्धि हो रही है। एचटी और एलटी के प्रशुल्क के बीच अन्तर भी कम हो गया है। इन अवयवों के अलावा पत्तन विद्युत संस्थापनाओं को मजबूत करने के लिए भी जारी पूँजी व्यय करता है। व्यय की प्रकृति जबकि समान हो सकती है, विभिन्न प्रकार के व्यय और व्यय की मात्रा वही (समान) नहीं रहते। इसलिए इस उपरिव्यव प्रभार को लागू करने का प्रस्ताव है।

(vi) उपयोगकर्ता चाहे तो सीधे टीएनईबी से विद्युत प्राप्त कर सकते हैं।

(vii) विद्युत अधिनियम में, वास्तव में आपूर्ति विद्युत के प्रभार के अलावा पत्तन विद्युत संस्थापनाओं का प्रावधान है, इसलिए पत्तन द्वारा प्रस्तुत और इस प्राविकरण के विचाराद्वीन प्रस्ताव व्यवस्थित है।

(viii) पत्तन की अपनी निजी खपत के प्रबोधन का मुद्दा कर्तमान प्रस्ताव के दायरे से बाहर है।

(ix) जबकि पत्तन विद्युत के लिए टीएनईबी को एचटी (III) (वाणिज्यिक) उपयोगकर्ताओं को लागू दरों पर प्रभारों का भुगतान कर रहा है, पत्तन द्वारा उपयोगकर्ताओं से एलटी (V) वाणिज्यिक दरों के आधार पर प्रभार लिए जाते हैं। इसके अलावा पत्तन को अधिकतम मांग प्रभार और अनुरक्षण के अन्य अनुबंधित प्रभारों की पूर्ति करनी पड़ती है। अतएव पत्तन द्वारा प्रावित प्रशुल्क और विद्युत के लिए टीएनईबी के प्रशुल्क के बीच तुलना युक्तिसंगत नहीं है।

(x) शीएसए-एसआईसीएल को विद्युत-प्रभार का भुगतान टीएनईबी प्रशुल्क में लागत की वसूली बिना हानि-लाभ आधार पर करने का प्रावधान है। अतएव, शीएसए-एसआईसीएल को भी प्रस्तावित उपरिव्यव का भुगतान करना चाहिए।

4. प्रस्ताव की प्रारम्भिक जांच पड़ताल के आधार पर टीपीटी से विभिन्न बिन्दुओं पर अतिरिक्त मूल्यनाएँ प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था। टीपीटी ने प्रस्तावित लेवी के कानूनी प्रावधानों, जैसाकि पहले उल्लेख किया गया है, के संदर्भ से अपने स्पष्टीकरण प्रस्तुत किए हैं। इसके अतिरिक्त टीपीटी ने मिम्लिखित बातें कही हैं:

(i) विद्युत लागत उपयोग किए गए यूनिटों के अनुसार विभिन्न उपयोगिताओं के प्रभारित की गई है और संबंधित उपरिव्यव को प्रबंधन और सामान्य प्रशासन व्यय के बाग के रूप में लिया गया है। और पिछले सामान्य संशोधन प्रस्ताव के समय प्रस्तुत की गई लागत विवरणी में विभिन्न उप-गतिविधियों में समानुपातिक रूप से बंटवा दिया गया है।

(ii) वर्तमान प्रस्ताव सामान्य संशोधन प्रस्ताव को प्रस्तुत करने के बाद का है, इसलिए सामान्य संशोधन प्रस्ताव से इस लागत तत्व को बाहर रखने का कोई ब्रह्म ही नहीं उठता। तात्कालिक प्रस्ताव के उपयोगकर्ताओं से कुल संग्रह 47.57 लाख रुपये आता है और सामान्य संशोधन प्रस्ताव पर इसका प्रभाव लगभग नग्या होगा और इसलिए यह वर्तमान प्रस्ताव के लिए सम्बद्ध अवधार नहीं है।

(iii) टीएनईबी द्वारा बिजली की प्रावित प्रति यूनिट दर, प्रति एचटी प्रशुल्क के अनुसार रु. 5/- प्रति यूनिट है और रु. 300/- प्रति कि वो ए प्रति माह का अधिकतम मांग प्रभार तथा मीटर किराया सम्मिलित करने के बाद प्रभावी दर रु. 6.20 प्रति यूनिट आती है। किन्तु पत्तन टीएनईबी द्वारा निर्धारित एलटी प्रशुल्क (अर्थात पहले 200 यूनिट के लिए रु. 5.30 प्रति यूनिट, 200 यूनिट से ऊपर रु. 5.80 + 5% विद्युत कर और निर्धारित प्रभार रु. 60/- एकत्रित करता है जिसमें किसी प्रकार के उपरिव्यव की वसूली नहीं है।

(iv) इसने पुष्टि की है कि पत्तन द्वारा किए गए, पत्तन कर्मचारियों द्वारा किए गए उपयोग और शीएसए-एसआईसीएल द्वारा उपयोग पर व्यय को इस गणना से बाहर रखा गया है।

5. इस प्रकरण में एक संयुक्त सुनवाई 19 फरवरी 2004 को टीपीटी परिसर में आयोजित की गई थी। संयुक्त सुनवाई में टीपीटी और संबंधित उपयोगकर्ताओं ने अपने-अपने पक्ष रखे।

6.1 जैसा कि संयुक्त सुनवाई में निर्णय लिया गया था, टीपीटी से अनुरोध किया गया कि वह विद्युत अधिनियम 2003 के प्रावधानों की तुलना में प्रस्तावित उपरिव्यव लागाने के लिए पत्तन की सहमता पर टीपीटी द्वारा प्राप्त की गई कानूनी राय की एक प्रति भेजे और वर्ष 2003-04 (सं. अनु.) और 2004-05 (ब.अनु.) के लिए संबंधित लागत विवरणियां प्रस्तुत करे।

6.2 टीपीटी ने अपेक्षित लागत विवरणियां और प्रस्तावित उपरिव्यव लागाने के लिए पत्तन की सहमता पर टीपीटी द्वारा प्राप्त की गई कानूनी राय की एक प्रति भी प्रस्तुत की। टीपीटी के कानूनी सलाहकार द्वारा की गई कुछ मुख्य प्रेक्षाएं नीचे पुनः की जाती हैं:

“मैं यह भी सुझाव द्यूग कि सेवा प्रभार वसूल करने के मुद्दे पर यदि आप टीएनईबी प्राविकारियों की भी राय ले लें तो बेहतर होगा। मेरा अनुमान है कि विद्युत अधिनियम के अन्तर्गत लाइसेंस धारियों को अतिरिक्त राशि एकत्रित करने हेतु अनुमति है। किन्तु इस अधिनियम में लाइसेंसधारी से केवल उनका अभिप्राय होगा जिन्हें विद्युत पारेवण और वितरण के लिए लाइसेंस प्राविकारियों द्वारा दिया गये है। संबंधित प्राविकारियों से इस पर समर्वन ले लेना, भेंटी राय में काफी सहायक होगा।”

“यदि अनुमेय हो तो हम प्राविकारियों से अनुमोदन प्राप्त कर सकते हैं जो बाद में कोई कठिनाई छोने पर सहायक हो सकता है। सभी संबंधनाओं में टीएमपी द्वारा बुलाई गई बैठक के दौरान विद्युत बोर्ड की ओर से प्रतिनिवित होगा। इस मुद्दे पर वर्दी पर विचार-विमर्श हो सकता है।”

“जहाँ तक अन्य पत्तन उपयोगकर्ताओं के साथ, जो प्रधानतः सभान हैं, किए गए अनुबंध की बात है, मुझे लगता है कि धारा (ii) आपकी मदद के लिए आयेगी । यह धारा विनिर्देश करती है कि लाइसेंसधारी पट्टे की अवधि के दौरान हस्तान्तरित भूखण्ड या उसके ऊपर निर्माण किए जाने वाले भवन के संबंध में सभी दरों, करों और प्रत्येक प्रकार के प्रभार का भुगतान करेगा जो आज देय है या आज के बाद पट्टादाता या पट्टादारक द्वारा, देय हो जाएंगे । इस प्रधानान का अर्थ होगा कि कोई भी दरे कर या प्रभार, जो संशोधित हैं- संशोधित किए जा रहे हैं या संशोधित किए जाने हैं, पट्टादारक द्वारा देय होंगे ।”

“अनुबंध के इस विशेष कालम में, यह विशेष रूप से लिखा हुआ है कि लाइसेंसों पर लगाए गए प्रभार टीएनईबी की अनुसूचित दरों के अनुसार होंगे । इसलिए भेरी राय में यह अतिरिक्त कसूली के लिए कोई प्रयास किया जाता है तो मेसर्स पीएसए एसआईसीएल लिमि. निश्चित रूप से अपने अधिकारों को वैध सिद्ध कर सकता है, और अनुबंध की धारा 6.1.8 में प्रदत के अतिरिक्त कसूली के लिए कोई प्रयास किया जाता है तो उससे अधिक कुछ भुगतान नहीं करता ।”

“मेरा यह सुझाव होगा कि प्रस्ताव को सभी उपयोगकर्ताओं के लिए, मेसर्स पीएसए एसआईसीएल लिमि. को छोड़कर जो अपने अनुबंध के द्वारा आपके साथ रक्षित है, लागू किया जा सकता है । वृद्धि की प्रतिशततम के बारे में मेरा अनुमान है कि इसे एक तर्क संगत अनुपात में होना चाहिए ।

7. इस प्रकरण में परामर्श से संबंधित प्रक्रिया इस प्राधिकरण के कार्यालय में रिकार्ड पर उपलब्ध है । प्राप्त टिप्पणियों के सारांश और संबंधित पक्षों द्वारा दिए गए तर्क संबंधित पक्षों को अलग से भेजे जाएंगे । ये विवरण हमारे वैबसाइट www.tariff authority.org पर भी उपलब्ध हैं ।

8. इस प्रकरण पर कार्रवाई के दौरान एकत्रित सूचनाओं की समग्रता के संदर्भ से निम्नलिखित स्थिति उमरती है :-

- (i) टीपीटी का प्रस्ताव अधिक्षेत्र के भौगोलिक क्षेत्र के भीतर विभिन्न प्रयोजनों से विद्युत के वितरण में सन्निहित उपरिव्यव खर्च की भरपाई के लिए नई प्रशुल्क मद आरम्भ करने के लिए है । यद्यपि पत्तन का लक्ष्य विद्युत के वितरण में लगी कम से कम प्रत्यक्ष लागत की वसूली करना है, इसने लेवी को 20% तक सीमित रखने का प्रस्ताव किया है क्योंकि वास्तविक लागत पर आधारित दर कथित रूप से बहुत अधिक है ।
- (ii) इस समय पत्तन अपने उपयोगकर्ताओं से, तमिलनाडु विद्युत बोर्ड (टीएनईबी) को दिए जा रहे प्रशुल्क के अनुसार लागू दरें ही वसूलता है । जैसाकि पत्तन द्वासा सही-सही उल्लेख किया गया है, टीएनईबी को दिए जा रहे विद्युत प्रभारों के साथ-साथ उल्लेख किया गया है, यह अपने क्षेत्र के बीतर विद्युत के वितरण हेतु आवश्यक संरचना के निर्माण एवं अनुरक्षण पर धन खर्च करता है । वर्तमान व्यवस्था में संबंधित उपरिव्यव खर्चों को सामान्य प्रशासनिक उपरिव्यव के भाग के रूप में समझा जाता है, और विभिन्न गतिविधियों में सामान्यात्मक रूप से बांट दिया जाता है । इसका अर्थ हुआ कि टीपीटी द्वारा अनुरक्षित विद्युत संस्थापनाओं से संबंधित व्यव टीपीटी की सभी गतिविधियों के प्रशुल्क के ऊपर फैला दिया जाता है । इस प्राधिकरण का सदा यह भत रहा है कि प्रभारों की व्यव टीपीटी की सभी गतिविधियों के प्रशुल्क से देखने पर टीपीटी द्वारा प्रस्तावित नजरिया इस प्राधिकरण की सामान्य न कि उनकी परामर्श वसूली की जाए । इस दृष्टिकोण से देखने पर टीपीटी द्वारा प्रस्तावित नजरिया इस प्राधिकरण की सामान्य विचारधारा के अनुरूप पाया गया है और उसे सेहतात्मक रूप से समर्थन दिया जाना चाहिए । कुछ उपरोक्ता संगठनों द्वारा की गई टिप्पणियों के प्रत्युत्तर भैं टीपीटी ने स्पष्ट किया है कि उपयोगकर्ता, चाहे तो, सीधे तमिलनाडु विद्युत बोर्ड से विद्युत प्राप्त कर सकते हैं । तथापि यह तकनीकी समाव्यता के अधीन होगी । इस बात को स्वीकार करना होगा कि जो संबंधित उपयोगकर्ता इस प्रकार की व्यवस्था के लिए इच्छा व्यक्त करेगा उसे इस व्यवस्था के लिए आवश्यक संस्थापनाओं के लिए निवेश करना होगा अथवा इस प्रकार की सुविधा के लिए विद्युत बोर्ड को भुगतान करना होगा ।
- (iii) जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है और टीपीटी द्वारा स्वीकार किया जा चुका है कि टीपीटी के दरमान के पिछले सामान्य संशोधन के समय विद्युत आपूर्ति से संबंधित उपरिव्यव खर्चों को सामान्य प्रशासन व्यव का भाग समझा गया था। उपरिव्यव व्यव खर्चों की भरपाई के लिए अन्य प्रशुल्कों की युनियनों के बिना इस मुकाम पर यदि कोई नई लेवी आरम्भ की जाती है तो निश्चित रूप से यह दोहरी गणना हो जाएगी । इस प्रकार की गणना का अन्य प्रशुल्क मदों पर प्रयाव बहुत थोड़ा या नगण्य हो सकता है और दोहरी गणना की अनुमति देने के लिए यह कोई वैधकारण नहीं हो सकता । यहाँ यह ध्यान देने योग्य है कि इस प्रकार के उपरिव्यव खर्चों को, इस प्राधिकरण द्वारा, अन्यत्र, दोहरी गणना की समावना समाप्त करने के लिए, नई प्रशुल्क मद का निर्धारण करते समय बाहर रखा गया था । ऐसा होते हुए, इस प्रकरण में यह उचित होगा कि टीपीटी के दरमान के अगले सामान्य संशोधन के समय, जो सितम्बर 2004 में अपेक्षित है, यदि अन्यथा ग्राह्य हो तो, प्रस्तावित लेवी आरम्भ कर दी जाए । इस प्रकार का प्रस्ताव तैयार करते समय टीपीटी, पत्तन द्वारा स्वयं उपयोग में लाई जाने वाली और अपनी आवासीय बस्ती में उपयोग की जाने वाली बिजली पर होने वाले व्यव की भरपाई के लिए उपयोगकर्ताओं से लेवी का भुगतान करने की अपेक्षा न करने का तूरीकोरिन थैम्बर ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्रीज के सुझाव पर भी विचार करें । इस प्रकार के व्यव को सामान्य प्रशासन उपरिव्यव ही समझा जा सकता है और उसे पत्तन की सभी गतिविधियों में सामान्यात्मक रूप से बांटा जा सकता है ।
- (iv) तूरीकोरिन थैम्बर ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्रीज ने इस प्रकार का प्रभार लगाने हेतु टीपीटी की सक्षमता पर विद्युत अधिनियम 2003 के संदर्भ से एक सहत्यार्थ मुक्त उठाया है । जबकि यह प्राधिकरण टीपीटी के प्रस्ताव का सिद्धांत रूप में समर्थन करता है, विद्युत के वितरण के बारे में पत्तन की वित्तीय स्थिति को नियन्त्रित व्यव करने की आवश्यकता है ताकि इस प्रकार की दरों को अनुमोदित करने की इस प्राधिकरण की सक्षमता स्थापित की जा सके । टीपीटी ने विद्युत अधिनियम 2003 के खंड 13 के प्राक्कारों पर भरोसा किया है । इस अधिनियम के खंड 13 के अनुसार टीपीटी जैसे स्थानीय प्राधिकरण को, विद्युत के वितरण के लिए लाइसेंस की आवश्यकता से छोट प्राप्त है । इस विद्युत अधिनियम के खंड 13 को साक्षातीय पूर्वक पढ़ने से यह स्पष्ट होता है कि इस प्रकार की मूल अपने आप नहीं मिल जाती है, बल्कि सम्मिलित सरकार की सिफारिश पर समुचित आयोग से इस आवश्य की एक अधिसूचना की आवश्यकता होती है । टीपीटी को छोट प्रदान करने वाला, किसी समुचित आयोग द्वारा जारी की गई कोई अधिसूचना रिकार्ड में नहीं है ।

टीपीटी ने, इसके आगे, विद्युत अधिनियम 2003 के खंड 184 का संदर्भ दिया है जो यह अनुबंधित करता है कि इस अधिनियम के प्रावधान केन्द्र सरकार के रक्षा और परमाणु ऊर्जा से संबंधित मंत्रालयों, विभागों और ऐसे ही समान मंत्रालयों या विभागों या उपक्रमों या बोर्डों या ऐसे मंत्रालयों और विभागों के नियंत्रणाधीन संस्थानों पर जिन्हें केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया हो, लागू नहीं होंगे। यदि इन प्रावधानों की टीपीटी पर अनुप्रयोजनता संदिध नहीं है, यह स्पष्ट नहीं है कि क्या केन्द्रीय सरकार से कोई औपचारिक अधिसूचना अपेक्षित होती या नहीं। अपने दावे के समर्थन में टीपीटी द्वारा प्रस्तुत की गई कानूनी सलाह निष्कर्ष नहीं है।

(v) टीपीटी द्वारा प्रस्तुत की गई कानूनी सलाह यह सुझाव देती है कि लाइसेंसवारकों को अतिरिक्त राशि एकत्रित करने की अनुमति है, जो वास्तव में टीपीटी का प्रस्ताव ही है। तथापि कानूनी राशि, यह उल्लेख करते हुए कि विद्युत अधिनियम के अनुसार लाइसेंस धारक से अधिग्राह केवल उनसे होगा जिन्हें पारेशण और वितरण के लिए प्राधिकारियों द्वारा लाइसेंस दिए गए हैं। अपने प्रस्ताव के समर्थन में, टीपीटी ने, टीएनईबी द्वारा जारी की गई विद्युत आपूर्ति की शर्तों और निवन्धनों के संबंधित अंशों की प्रति भेजी है। इस दस्तावेज की धारा 31.03(i) स्पष्टीय पर हानि-लाभ रहित अधार पर, उपरोक्त की लागत वसूलने की अनुमति प्रदान करती है। तथापि यह प्रावधान कथित रूप से वाणिज्यिक या कार्यालय या आवासीय परिसरों के मामले में लागू है जहाँ हाई टैक्षन या लो टैक्षन विद्युत आपूर्ति मूलरूप से परिसर के निर्माता या प्रोन्टकर्ता के नाम प्राप्त की जाती है जो बांद वे, परिसर का स्वामित्व या तो सम्पूर्ण रूप से विभिन्न व्यक्तियों को हस्तांतरित कर देता है या आंशिक रूप से विभिन्न व्यक्तियों को सौप देता है और शेष पट्टे के लिए रख लेता है। यह बहुत स्पष्ट नहीं है कि क्या पत्तन न्यास इस परिभाषा में खास उत्तरता है। टीपीटी का प्रस्ताव टीएनईबी की टिप्पणियों के लिए उन्हें भेजा गया था। किन्तु हमें उनसे कोई प्रत्युत्तर नहीं मिला है।

(vi) टीपीटी ने पीएसए एसआईसीएएल को भी प्रस्तावित लेवी की पुंच में समेटने का प्रस्ताव किया है। पीएसए एसआईसीएएल और टीपीटी के बीच लेन-देन एक विशिष्ट बीओटी लाइसेंस अनुबंध द्वारा संचालित होता है। पीएसए एसआईसीएएल ने प्रस्तावित लेवी को इस दावे के साथ चुनौती दी है कि उसे, बीओटी अनुबंध के अनुसार, टीएनईबी की अनुसूचित दरों के अधार पर प्रमाणों की प्रतिष्ठापित करनी पड़ेगी। बीओटी अनुबंध की धारा 61.8 विद्युत और जल आपूर्ति व्यवस्था को अनुसूचित करती है। संबंधित धारा स्पष्ट रूप से विनिर्देश करती है कि लाइसेंसधारक पर लगाए गए प्रधार टीएनईबी की अनुसूचित दरों के अनुसार होंगे। टीपीटी द्वारा प्राप्त की गई कानूनी राशि में भी इसी स्थिति की पुष्टि की गई है। यह मानसे हुए कि विद्युत आपूर्ति के लिए टीएनईबी द्वारा जारी की गई शर्तें और निवन्धन कैद हैं और इन शर्तों व निवन्धनों की धारा 31.03 टीपीटी के लिए प्रासंगिक होगी, यह स्पष्ट नहीं है कि क्या शब्द “टीएनईबी की अनुसूचित दर” में प्रस्तावित उपरिव्यय लेवी सम्प्रिलित होगी या नहीं। पुनर्शब्द, इस मुद्दे को टीपीटी और टीएनईबी द्वारा स्पष्ट नहीं किया गया है।

(vii) पिछले पैराग्राफों में जो कुछ बताया गया है, उसकी दृष्टि से, यह स्पष्ट होता है कि टीपीटी के प्रस्ताव को इस मुकाम पर दो कारणों से स्वीकार नहीं किया जा सकता। प्रथमतः उपरिव्ययों को दो बार भिन्ना भिन्ना माया है। दूसरे, प्रस्तावित प्रशुल्क व्यवस्था को अनुमोदन प्रदान करने से पहले इस प्रकारण ने उठने वाले कानूनी मुद्दों को वरीयता से सुलझाया लिया जाए। पत्तन के विधिक सलाहकार ने सुझाव दिया है कि टीएनईबी की राशि ले ली जाए। पत्तन इस दिशा में कार्रवाई कर भी ले लो तो भी हमें विश्वास नहीं है कि केवल इतना ही पर्याप्त होगा। पत्तन इस मुद्दे को तमिलनाडु विद्युत विनियायक आयोग के सौप सकता है और इस मामले में सही कानूनी स्थिति पर उनका मार्गदर्शन प्राप्त कर सकता है। जैसाकि पहले ही उल्लेख किया जा चुका है कि इस प्राधिकरण की मनशा टीपीटी के दृष्टिकोण का सिद्धांततः समर्थन तो करना चाहता है किन्तु लेवी लगाने संबंधी विचार-विमर्श को टीपीटी के दरमान में अगले सामान्य संशोधन तक ठालना चाहते हैं बरतें टीपीटी प्रस्ताव दोबारा प्रस्तुत करने से पहले कानूनी मुद्दों पर उपरोक्त डंग से स्पष्टीकरण प्राप्त कर ले।

10. परिणामस्वरूप और ऊपर दिए गए कारणों से और समग्र विचार विमर्श के अधार पर, यह प्राधिकरण, विद्युत आपूर्ति से संबंधित उपरिव्यय खर्चों की घरपाई के लिए इस मुकाम पर नई लेवी लगाने के बारे में टीपीटी के प्रस्ताव को अस्वीकार करती है। विभिन्न कानूनी मुद्दों पर स्पष्टीकरण के अधीन, टीपीटी को, फिर भी सलाह दी जाती है कि वह प्रस्तावित लेवी को, अपने दरमान के अगले सामान्य संशोधन तक में अपेक्षित है, से संबंधित प्रस्ताव का भाग बना ले।

अ.ल. बोंगिरवार, अध्यक्ष

[विज्ञापन/III/IV/143/04/असा.]

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

NOTIFICATION

Mumbai, the 19th May, 2004

No. TAMP/79/2003-TPT.—In exercise of the powers conferred by Sections 49 and 50 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby disposes of the proposal received from the Tuticorin Port Trust (TPT) for fixing a levy to recover overhead charges in respect of electricity charges as in the Order appended hereto.

No. TAMP/79/2003-TPT

The Tuticorin Port Trust (TPT)

Applicant

ORDER

(Passed on this 4th day of May 2004)

This case relates to a proposal received from the Tuticorin Port Trust (TPT) for fixing a levy to recover overhead charges in respect of electricity charges.

2.1. The TPT has made the following main points in its proposal:

(i). The charges in respect of electricity consumed by the consumers/ users is collected as per the tariff prescribed by the Tamil Nadu Electricity Board (TNEB).

In case of PSA SICAL, a separate transformer exists, hence in addition to consumption charges, Maximum Demand charges and meter rent are also collected from PSA SICAL.

(ii). While distributing the electricity to the consumers, the port incurs heavy expenditure on Maximum Demand Charges, infrastructure provided for distribution, distribution loss and operation and maintenance cost. Hence, it is proposed to recover overhead charges from the users. Since the rate worked out by the port in June 2003 to recover the overhead charge was not acceptable to the members of its Board of Trustees, a three member Committee was constituted to recommend the levy to be recovered as overhead charge in respect of the electricity consumed by users.

(iii). As per the cost calculation submitted by the Committee, 142.77 % is to be recovered from the PSA SICAL and 158.09% is to be levied on the electricity charges from other users to recover the total overhead charge. In this context, it has quoted that the electricity overhead charge levied by the COPT is at 291% and at the Jawaharlal Nehru Port Trust it is at 20%.

(iv). In view of the huge indirect cost involved, the Committee subsequently proposed to recover only the direct fixed cost @ 52.55% from port users and 33.62% from the PSA SICAL.

(v). Two members of the Committee objected to this reduced rate also and suggested to recover a levy at a nominal rate of 5%. The members of the Committee pointed out that the users would like to avail power supply directly from the Tamil Nadu Electricity Board after obtaining No objection Certificate from the port.

2.2. The Board of Trustees of TPT has finally approved recovery of overhead charge @ 20% of the electricity bill from the port users, contractors, etc., on an adhoc basis. The port has stated that the proposed levy would be reviewed later.

3.1. In accordance with the consultative procedure adopted, a copy of the proposal was forwarded to the concerned user organisations for their comments.

3.2. The comments received from the above users were forwarded to the TPT as feedback information. In response, the TPT has furnished its comments as summarised below:

(i). As per the lease agreement executed with the TPT, the Tuticorin Steamer Agents' Association (TSAA) have to bear the tariff fixed by the port from time to time. Copy of the Agreement has been attached in support of its claim.

- (ii). As regards the observation of the TSAA that port has not furnished proper justification, it has clarified the port also incurs repairs and maintenance (which includes the establishment charges of the staff deployed) and depreciation cost on the electrical installation, in addition to the tariff paid to the TNEB. This has to be recovered from the users availing the facility.
- (iii). It has referred to various clauses of the Electricity Act, 2003 as reproduced below to clarify the legal provisions of the proposed levy:

Part - IV - Licensing

Section No.13 – Power to exempt

“The Appropriate Commission may on the recommendations of the Appropriate Government, in accordance with the national policy formulated under section 5 and in public interest direct by notification that subject to such conditions and restrictions, if any, and for such period or periods, as may be specified in the notification, the provisions of section 12 shall not apply to any local authority, Panchayat Institution, users’ association, co-operative societies, non-governmental organisations or franchisees.”

Section No.41

“Local authority” means any Nagar Panchayat, Municipal Council, Municipal corporation, panchayat constituted at the village, intermediate and district levels, body or port commissioners or other authority legally entitled to or entrusted by the Union or any State Government with, the control or management of any area or local fund”

Section No.184

“The provisions of this Act shall not apply to the Ministry or Department of the Central Government dealing with Defence, Atomic Energy or such other similar Ministries or Departments or undertakings or Boards or institutions under the control of such Ministries or Departments as may be notified by the Central Government”

As per the above provisions in the Electricity Act 2003, it is clear that the provision of obtaining license to be an authorized person to transmit, distribute the electricity, etc., shall not apply to any “Local authority” and the definition of the term “Local Authority” includes port commissioners apart from the other bodies.

- (iv). Further, it has also referred to the Terms and Conditions of Electricity Supply entered with the TNEB in support of its claim. Clause 31.03 (1)& (2) in this document reads as follows:

“The builder or promoter of the complex in whose name the supply continues, may be permitted to extend power supply to the individual owners of the flats etc. or to the lessees by installing sub-meters and to collect the cost of consumption of power from them on no profit or no loss basis (i.e. sharing of expenses of consumption of Electricity) and this shall not be treated as unauthorised extension of supply or sale of energy.”

The port is extending supply of power to users. As per this clause, the port can collect charges towards recovery of the expenditure incurred over and above the amount payable for consumption of electricity on no loss and no gain basis.

- (v). Maximum demand charge is continuously increasing and there has been substantial increase in maintenance and establishment charges also. The gap

between tariff of HT and LT has also narrowed down. Apart from these factors, the port also incurs huge capital expenditure for strengthening the electrical installations. While the nature of expenditure may be the same, the different types of expenditure and quantum of expenditure do not remain the same. Hence it is proposed to introduce this overhead charges.

- (vi). The users have option to avail power directly from the TNEB.
- (vii). The Electricity Act provides for fixed charges in addition to charges for actual electricity supplied, therefore, the proposal submitted by the port and being considered by the Authority is in order.
- (viii). The issue about monitoring port's own private consumption are outside the purview of the current proposal.
- (ix). While the port is paying the charges for electricity to TNEB at the rates applicable to HT (III) (commercial) consumers, the collections from the consumers by the port are on the basis of LT (V) commercial rates. In addition, the port has to meet the maximum demand charges and other incidental charges of maintenance, etc. Hence, comparison of the tariff levied by the port and the TNEB tariff for electricity charges is not relevant.
- (x). The PSA SICAL have to pay the electricity charges as per the TNEB tariff and the TNEB tariff provides for collection of cost on no profit no loss basis. Hence, the PSA SICAL should also pay the proposed overhead charge.

4. Based on a preliminary scrutiny of the proposal, the TPT was requested to furnish additional information on various points. The TPT has furnished clarifications with reference to the legal provisions of the proposed levy as mentioned earlier. In addition to that, the TPT has stated the following main points:

- (i). The electricity cost has been charged to various sub-activities as per the units consumed; and, the related overhead expenses are treated as part of management and general administration expenditure and apportioned to the various sub-activities in the cost statements furnished at the time of the last general revision proposal.
- (ii). The current proposal is subsequent to the submission of the general revision proposal, therefore, the issue of exclusion of this cost element from the general revision proposal does not arise. The total collection from users from the instant proposal comes to Rs.47.57 lakhs and the impact of this on the general revision proposal will be almost nil and hence the same is not a relevant factor for the current proposal.
- (iii). The unit rate of electricity levied by the TNEB is Rs.5/- as per HT tariff and the effective rate works out to Rs.6.20 per unit after including the maximum demand charges of Rs.300/- per KVA per month and the meter rent. However, the port collects LT tariff fixed by the TNEB (i.e. Rs.5.30 for first 200 unit, Rs.5.80 above 200 unit plus 5% E. Tax and fixed charges of Rs.60/-) without recovery of any overhead charge.
- (iv). It has confirmed that the cost attributable to consumption by the port, port employees, and the PSA SICAL have already been excluded in this computation.

5. A joint hearing in this case was held on 19 February 2004 at the TPT premises. At the joint hearing, the TPT and the concerned users have made their submissions.

6.1. As decided in the joint hearing, the TPT was requested to forward copy of the legal opinion obtained by it on the competence of the port to levy the proposed overhead

charge vis-à-vis the provisions in the Electricity Act, 2003 and to furnish relevant cost statements for the years 2003-04 (RE) and 2004-05 (BE).

6.2. The TPT has furnished the requisite cost statements and a copy of the legal opinion obtained by it on the competence of the port to levy the proposed overhead charge. Some of the main observations made by the legal advisor of the TPT are reproduced below:

"I would also suggest that you 'd better collect an opinion from T.N.E.B. authorities on the issue of collection of service charges. I guess under the Electricity Act, the licencees are allowed to collect an extra sum. But the licensee in the Act would mean only those who are given licence by the Authorities for transmitting and distributing. It would be helpful, in my opinion, to have an endorsement from the concerned authorities."

"If permissible, we can get an approval from the Authorities, which would be conducive in case of any predicament lateron. In all possibilities there would be representation from the electricity board during the meeting convened by TAMP. This issue could discussed thereitself."

"As far as the agreement entered in to with other port users, which are predominantly uniform, I find that clause (ii) would come into your rescue. This clause specifies that the licensee shall, during the period of lease pay all rates, taxes and charges of every description now payable or hereafter becomes payable by the lesser or lessee in respect of the demised plot of plot or the buildings to be erected thereupon. This provision would mean that any rates, taxes or charges revised, being revised or to be revised shall also be paid by the lessee."

"In this particular column in the agreement, it is specifically mentioned that the 'charges' levied on the licenses shall be as per the schedule rates of T.N.E.B. Therefore in my opinion M/S PSA SICAL Ltd. can definitely vindicate their rights in case of any attempt for additional collection and not to pay anything extra other than what is granted in the agreement in the clause 6.1.8."

"I would suggest that the proposal could be implemented with a proportionate hike, to all the users, except M/S PSA SICAL Ltd, who is protected by their agreement with you. Speaking about the percentage of hike, I guess, it has to be in the reasonable ratio."

7. The proceedings relating to consultation in this case are available on records at the office of this Authority. An excerpt of the comments received and arguments made by the concerned parties will be sent separately to the relevant parties. These details are also available at our website www.tariffauthority.org.

8. With reference to the totality of information collected during the processing of this case, the following position emerges:

- (i). The proposal of TPT is for introduction of a new tariff item to cover the overhead expenses involved in distribution of electricity for various purposes within its geographical area of jurisdiction. Although the objective of the port is to recover at least the direct cost incurred in distribution of electricity, it has proposed to restrict the levy at 20% since actual cost based rate is reportedly very high.
- (ii). Presently, the port recovers from its users the tariff being paid to the Tamilnadu Electricity Board (TNEB) at the applicable rates. As correctly pointed out by the port, in addition to payment of electricity charges to the TNEB, it also incurs expenditure on creation and maintenance of the required infrastructure for distribution of electricity within its area. In the existing arrangement the related overhead expenses are treated as part of the general administrative overheads

and apportioned to the various activities. This means the expenditure relating to the electrical installations maintained by the TPT is spread over the tariff for all the activities of the TPT. This Authority has always held that recovery of charges should commensurate with the services / facilities provided and such charges are to be recovered from the concerned users instead of resorting to indirect recovery. Viewed from this perspective, the approach proposed by the TPT is found to be in line with the general thinking of this Authority and deserves to be endorsed in principle. In response to the comments made by some of the user organizations, the TPT has clarified that the users have an option to avail power directly from Tamil Nadu Electricity Board. This will, however, be subject to technical feasibility. It has to be recognized that the concerned users opting for such an arrangement would have to necessarily invest in the required installations or pay the Electricity Board for creation of such facility.

(iii). As mentioned above and conceded by the TPT, the overhead expenses related to electric supply were treated as part of general administration expenditure at the time of the last general revision of Scale of Rates of TPT. If a separate levy to recover the overhead expenses is introduced at this juncture without reworking other tariff, it will definitely be a double counting. The impact of such a review on other tariff item could only be marginal or negligible cannot be a valid reason for allowing double counting of overheads. It is noteworthy that such overhead expenses are excluded by this Authority while fixing new tariff items elsewhere in order to remove the possibility of double counting. That being so, it will be appropriate in this case to introduce the proposed levy, if otherwise admissible, at the time of the next general revision of Scale of Rates of TPT which is due in September 2004. While preparing such a proposal, TPT may consider the suggestion made by the Tuticorin Chamber of Commerce and Industry about not requiring the users to pay the levy on the expenditure incurred for the electricity consumed by the port for its own use and for residential colony. Such expenditure can continue to be treated as general administrative overheads and apportioned to all the activities of the Port.

(iv). The Tuticorin Chamber of Commerce and Industry has raised an important issue about the competence of the TPT to levy such a charge with reference to the provisions in the Electricity Act, 2003. While this Authority endorses in principle the proposal of TPT, the legal position of the port in relation to distribution of electricity needs to be clarified unambiguously so that the competence of this Authority to approve such rate can be established. The TPT has relied on the provisions of Section 13 of the Electricity Act 2003 which exempts a local authority like TPT from the requirement of having a license for distribution of electricity. A careful reading of Section 13 of the Electricity Act reveals that such an exemption is not automatic but, requires a notification to that effect from the Appropriate Commission on the recommendations of the Appropriate Government. No such notification issued by the Appropriate Commission exempting TPT is available on record.

The TPT has further referred to Section 184 of the Electricity Act 2003 which stipulates that the provisions of the Act shall not apply to the Ministry or Department of Central Government dealing with defence, atomic energy or such other similar Ministries or departments or undertakings or Boards or institutions under the control of such Ministries or departments as may be notified by the Central Government. While applicability of this provisions to TPT is not in doubt, it is not clear whether any formal notification to this effect would be required from the Central Government. The legal advice furnished by the TPT in support of its contention is not conclusive.

(v). The legal advice submitted by the TPT suggests that the licensees are allowed to collect an extra sum which, in fact, is the proposal of the TPT. The legal

opinion, however, qualifies this position by mentioning that the licensee as per the Electricity Act will mean only those who are given license by the Authorities for transmitting and distribution. In support of its proposal, the TPT has forwarded a copy of the relevant portion of the terms and conditions of electric supply issued by the TNEB. Clause 31.03 (i) of this document clearly permits collection of cost of consumption on no profit or not loss basis. This provision is, however, stated to be applicable in case of commercial or office or residential complexes where high tension or low tension power supply is availed originally in the name of builder or promoter of the complex who subsequently transfers ownership of the complex either entirely to different individuals or partly to different individuals retaining the balance for lease. It is not very clear whether the Port Trust will fit into this definition. The proposal of TPT was forwarded to the TNEB for their comments, but we have not received any response from them.

(vi). The TPT has proposed to cover the PSA SICAL also within the ambit of the proposed levy. The transactions between PSA SICAL and TPT are governed by a specific BOT license agreement. The PSA SICAL has challenged the proposed levy claiming that it has to reimburse charges based on the scheduled rates of TNEB as per the BOT agreement. Clause 6.1.8 of the BOT agreement regulates power and water supply arrangement. The relevant clause clearly specifies that charges levied on the licensee shall be as per the scheduled rate of the TNEB. The legal opinion obtained by TPT also endorses this position. Presuming that the terms and conditions of supply of electricity issued by the TNEB is valid and clause 31.03 of such terms and conditions will be relevant to TPT, it is not clear whether the term 'scheduled rate of TNEB' will include the proposed overhead levy. Again, this issue is not clarified by the TPT and the TNEB.

(vii). in view of what has been explained in the preceding paragraphs, it becomes clear that the proposal of TPT cannot be approved at this juncture for two reasons. Firstly, the overheads are counted twice. Secondly, the legal issues arising in this case need to be frontally addressed before approving the tariff arrangement proposed. The legal advisor of the port has suggested to obtain an opinion from TNEB. While the port may take necessary action in that direction, we are not sure whether this alone would be sufficient. The Port may also refer the issue to the Tamil Nadu Electricity Regulatory Commission and obtain their guidance on the correct legal position in this matter. As mentioned earlier, this Authority is inclined to endorse the approach of TPT in principle but defer consideration of introduction of levy till the next general revision of Scale of Rates of the TPT subject to the legal issues getting clarified in the manner mentioned above by TPT before they resubmit the proposal.

9. In the result, and for the reasons given above, and based on a collective application of mind, this Authority rejects the proposal of the TPT for introduction of a new levy to cover overhead expenses relevant to electric supply at this juncture. Subject to clarifications on the various legal issues, the TPT is, however, advised to include the proposed levy as a part of its proposal for the next general revision of its Scale of Rates which is due in September 2004.

A. L. BONGIRWAR, Chairman
[Advt./III/IV/143/04 Exty.]